ही प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के समस्त कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, बम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय टंककों की संख्या को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा था ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली ने जनवरी, 1991 में तथा फिर दिसम्बर, 1992 में टंककों के कुछेक पद भरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय का अनुमोदन मांगा था ।

(ङ) प्रतीक्षा सूची को शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली वर्तमान टंककों से कार्य पूरा करने की स्थिति में है ।

आय-कर से छूट

2612. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण समितियों/संगठनों को लाटरियों के मामले में कर के भुगतान से विमुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कल्याण समितियों/संगठनों ने इस संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है ; और

(घ) क्या कर से छूट प्राप्त इन संगठनों/कल्याण समितियों के कार्यकरण के संबंध में कोई जांच की गई है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति) : (क) से (घ) चूंकि वेलफेयर सोसाइटियों/संगठनों जिनके बारे में सूचना मांगी गई है, के नाम नहीं दिए जाते हैं इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

लाटरी विजेताओं से आयकर लिया जाना

2613. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरी विजेताओं की सम्पत्ति सैन्ट्रल रजिस्टर में सूचीबद्ध न किए जाने और विवरणी दायर न किए जाने के कारण आयकर के अपवंचन के मामले में अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन चूकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) यह कहना सही नहीं है कि लाटरी विजेताओं द्वारा आयकर अपवंचन किया जाता है क्योंकि उनकी सम्पत्तियों की केन्द्रीय रजिस्टर" में प्रविष्टि नहीं की जाती है ; वस्तुत इस प्रयोजन के लिए किसी "केन्द्रीय रजिस्टर" को रखने की पद्धति नहीं है। यह भी सही नहीं है कि ऐसे लाटरी विजेताओं की विवरणियां दायर न करने के कारण अपवंचन होता है, क्योंकि लाटरी के जीतने पर कर 40% की दर पर स्रोत पर काटा जाता है, जोकि वह दर है जो इस प्रकार के स्रोत की आय पर लागू होती है । इसलिए ऐसे लाटरी विजेता अपनी आय विवरणियां चाहे दायर करते हैं अथवा नहीं करते हैं, लेकिन इस कारण से कर अपवंचन नहीं हो सकता है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लाटरी पुरस्कार विजेताओं से आयकर की वसूली में सुधार लाने की दृष्टि से आयकर अधिनियम, 1961 में एक उपबंध अधिनियमित किया गया है, जिसके अन्तर्गत लाटरी के जीतने से प्राप्त की गई रकम से स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है । इसके अलावा, लाटरी की जीतने की रकम से किसी व्यय के प्रति कोई कटौती करना अनुमत्य नहीं है तथा ऐसी जीती गई रकम 40% की

समान दर पर कराधेय है, जो कि इस प्रकार की आय पर लागू होने वाली दर है। इसके साथ ही, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही उपाय किए गए हैं कि कर की कटौती ठीक प्रकार से स्रोत पर की जाती है तथा वार्षिक विवरणियां विधिवत रूप से दायर की जाती हैं ।

PMOs role in framing policy tor disinvestment

2614. SHRI MENTARY PADMA-NABHAM: Will the Minister of FIN ANCE be pleased to state:

(a) what was the role of the PMO in formulating and implementing policies regarding disinvestment and sale of shares of public sector unit recently; and

(b) what was the strategy adopted for sale of shares of various public sector units?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The Prime Minister's Office did not either formulate or implement the policy regarding disinvestment and sale of shares of public sector units. The formulation or implementation of policies is done by the concerned Departments/Ministries who obtain Cabinet decision wherever required.

The entire disinvestment policy has been clarified in detail and comprehensively by the Finance Minister in his Statement in response to Calling Attention Notice in the Rajya Sabha on the 6th August, 1993.

Reorganisation of Financial Institutions Questions

2615. SHRI MENTAY PADMANA-BHAM!: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Government will consider re-organisation of all public 584 R.S.—'7 financial institutions involved only m long term lending activities like the IDBI, IFCI, ICICI, SCICI, etc.;

(b) whether these organisations have submitted proposals to move to activities in the financial sector, which are very distant from the original intent of their respective characters;

(c) what is Government's reaction to the need to change the ethos of these public financital institutions;

(d) whether it is a fact that the managements of these institutions operate in an independent way; and

(e) if so, what isafeguards Govern ment have to monitor and scrutinise and check the activities and direc tions of these large public financial institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (c) Since IFCT, ICICI and SCICI are non-governmental companies, the question of theid re organisation by Government does not arise. However, Government has a proposal at hand for modifying the IDBI Act in order to enable it to raise the resources from the market. The original character and objectives of IDBI as the principal financial institution will, however, continue.

(d) and (e) The general superintendence, directions and management of the affairs and business Of the Industrial Development Bank of India (IDBI) vests in the Board of Director which is constituted by the Central Government. The Board discharges its functions on business principles with due regard to public interest. The management of IDBI operates in an independent manner, and the bank in the discharge of its functions is guided by such directions given to it in matter of policy involving public interest. IFCI, ICICI